चिंता का विषय : खरीफ फसलों के एमएसपी पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

05 अक्टूबर, 2018

द हिन्दू

''अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किसानों के लिए बेहतर साबित नहीं होती हैं।''

खरीफ के मौसम में कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा के महीने भर के भीतर, एनडीए सरकार ने बुधवार को रबी फसलों के लिए प्रस्तावित एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के पहले भाग के दौरान एमएसपी बढ़ाने में सतर्क दृष्टिकोण से तेज बदलाव को दर्शाती है।

नवीनतम वृद्धि उदार हैं, भले ही वे खरीफ फसल के लिए तय किये गये मूल्य की तुलना में मध्यम हैं। तुलनात्मक रूप से, पिछले खरीफ सीजन के एमएसपी पर सबसे ज्यादा वृद्धि अनाज रागी के लिए 52.5% थी। अब रबी फसलों के लिए सीजन-दर-सीजन में बढ़ोतरी के लिए 20.6% है।

गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल 105 रुपये यानी 6.1 फीसदी बढ़ाकर 1,840 रुपये कर दिया गया है। गेहूं के साथ चने और सरसों का उत्पादन उत्तर भारतीय राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होता है।

इन राज्यों में पिछले कुछ महीनों में किसानों ने व्यापक प्रदर्शन किया है जिसमें कल का प्रदर्शन भी शामिल है। कृषि उपज की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों में रोष है। उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोडने पड़े थे।

आंदोलनकारी किसान पेट्रोल और बिजली बिलों में कमी, एमएसपी व्यवस्था को कानूनी दर्जा देने, स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने, सभी फसलों का ऋण माफ करने, किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तों में बदलाव करने और दिल्ली-एनसीआर में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे।

सरकार से मांगें मानने का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों का गुस्सा किस हद तक शांत होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई फसलों की एमएसपी में वृद्धि 2017-18 से 2018-19 के बीच उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी से कम है।

सरसों का एमएसपी 200 रुपये बढ़ाकर 4,200 रुपये कर दिया गया है, जबकि चने के एमएसपी में 220 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चने का एमएसपी अब 4,620 रुपये हो गया है। इसी तरह मसूर के एमएसपी में 225 रुपये की वृद्धि की गई है।

जौ का एमएसपी 30 रुपये बढ़ाकर 1,440 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन कीमतों के साथ, सरकार ने अपने वादे को पूरा कर दिया है, अर्थात किसानों को उत्पादन की लागत से कम से कम 150% की कीमत मिल जाएगी और उनकी आय समय के साथ दोगुनी हो जाएगी।

नवंबर में रबी फसल रोपी जाएगी, जिसके दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान (क्रमशः गेहूं और सरसों के बड़े उत्पादक) इसमें सबसे ऊपर होंगे। जाहिर है, अब यह उम्मीद की जा रही है कि नए एमएसपी अपने किसान-अनुकूल प्रमाण-पत्रों को आगे बढ़ाएंगे और इसके संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे।

सरकार का कहना है कि रबी और खरीफ की फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को 626 अरब रुपये की अतिरिक्त आय होगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गेहूं का एमएसपी ए2+एफएल उत्पादन लागत से 112 फीसदी अधिक है।

चने के मामले में यह एमएसपी ए2+एफएल उत्पादन लागत की 75.2 फीसदी और सरसों के मामले में 89.9 फीसदी अधिक है।

यह कोई संयोग नहीं है कि सरकार यह फैसला हजारों नाराज किसानों का सड़क पर उतरने के एक दिन बाद घोषित किया है। यह उन उदाहरणों की एक लंबी कड़ी में नवीनतम है जो अंतर्निहित कृषि संकट के अस्तित्व को संकेत देते हैं।

लेकिन, ऐसी स्थिति केवल कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त कीमतों की कमी के कारण नहीं हुई है, बल्कि उर्वरकों और डीजल जैसे इनपुट की लागत में वृद्धि भी इसके लिए जिम्मेदार है। भारत के कृषि क्षेत्र में कई तनाव बिंदु हैं और जमीनी-स्तर पर खरीद अक्सर निर्धारित समर्थन मूल्यों पर नहीं होती है।

धान को छोड़कर, कुछ हद तक, गेहूं, एमएसपी फॉर्मूला सरकार द्वारा पर्याप्त प्रत्यक्ष खरीद की अनुपस्थिति में ज्यादातर फसलों के लिए काम नहीं करता है। कपास के लिए बाजार की कीमतें वर्तमान में एमएसपी के करीब हैं, लेकिन व्यापारियों का मानना है कि यू.एस.-चीन व्यापार युद्ध के कारण निर्यात मांग बढ़ेगी।

एक मजबूत तंत्र जो वास्तव में किसानों को फसलों के लिए घोषित एमएसपी प्राप्त करने में मदद करता है, वह एक मूल्य कमी भुगतान योजना और एक निजी खरीद योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

लेकिन यह अभी भी एक शुरूआती चरण में है और पर्याप्त नहीं है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से प्रतिबंधित व्यापार नीतियों और अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेपों को संबोधित करने के लिए जो उत्पादकता में वृद्धि को रोकती हैं।

* * *

GS World टीम...

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, फसल की उचित कीमत दिलाने और फसल की लागत को कम करने में लगी हुई है।
- बीते चार वर्षों में मोदी सरकार ने किसान कल्याण को लिए अनेक कदम उठाए हैं।
- अभी कुछ दिनों पहले ही खरीफ की फसलों की एमएसपी डेढ़ गुना से अधिक करने बाद मोदी सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का ऐलान किया है।

नाबार्ड की हालिया रिपोर्ट

- देश में किसानों की आमदनी सालाना 12 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 10.4 फीसदी की वृद्धि दर की ही जरूरत है।
- सरकार ने इस लक्ष्य को पाने के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं, जिनमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के अलावा अन्य कई उपाय किये हैं, ताकि किसानों की अतिरिक्त आमदनी हो सके।
- नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लघु व सीमांत किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इससे स्पष्ट है कि आय को दोगुना करने के लक्ष्य को समय से पा लिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 48 फीसदी किसान परिवार हैं। वर्ष 2015-16 में प्रति परिवार उनकी सालाना आमदनी 1.07 लाख रुपये हो गई, जो उन्हें खेती, पशुधन, गैर कृषि गतिविधियों और अन्य तरह के रोजगार से हुई।
- वर्ष 2012-13 में यह आय 77.11 हजार रुपये थी। 29 राज्यों में से 19 में यह दर 12 फीसदी से भी उपर है, जबकि 15 राज्यों में यह 10.5 फीसदी है।
- रिपोर्ट के मुताबिक देश के 52 फीसदी किसान ऋण से ग्रसित हैं।

क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी, 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- उत्पाद की लागत क्या है?
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है?
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है?
- मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है?
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. एमएसपी (MSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. MSP फार्मूले के द्वारा प्रत्यक्ष खरीद नीति अधिकांश फसलों तक विस्तारित है।
2. भारत में कृषि खरीद अधिकतर समर्थन मूल्यों पर होती है।
3. पिछले वर्ष रागी के MSP में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. MSP में 2017-19 के बीच वृद्धि लागत में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है।
2. MSP का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।
3. देश में सभी कृषि फसलों का MSP जारी किये जाते हैं।
4. गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा घोषित किये जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित में से किन-किन मदों को एमएसपी में शामिल करने हेतु स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गई?

1. डीजल
2. खाद
3. बीज
4. ब्याज
5. परिश्रमिक

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) 2, 3 और 4
(b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

नोट :

04 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(d), 3(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''भारत में कृषि क्षेत्र में कई तनाव बिन्दु अंतर्निहित है, जो कृषि संकट के अस्तित्व का संकेत दे रहे हैं।'' आप उपर्युक्त कथन से कहाँ तक सहमत है? (250 शब्द)